औद्योगिक विकास :

- आगरा, मेरठ, मथुरा और गोरखपुर में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना।
- प्रदेश में 10 लाख स्टार्टअप योजनाएं आरंभिक स्थिति में तैयार।
- उद्योग एवं पूंजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 लागू।
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे योजना के लिए जमीन क्रय, विकास होगा।
- डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर जरी इंडस्ट्री का काम पूरा, ट्रेनिंग सुविधा उपलब्ध।
- देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में शीघ्र।

अपना गांव :

- आईसीडीएस, मनरेगा एवं पंचायतराज द्वारा 10,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण होगा।
- मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू।
- गंगा एक्शन प्लॉन के तहत 25 जिलों के 1627 गांवों में 3.98 लाख टायलेट्स का निर्माण।
- 9765 गांव खुले में (ओडीएफ) शौचमुक्त।
- ग्रामीण इलाकों में पेयजल के लिए 58,979 हैंडपंपों का रिबोर एवं मरम्मत कराया गया।

संस्कृति-सभ्यता केन्द्र :

- गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या और विंध्याचल, चित्रकूट व इलाहाबाद के विकास के लिए धन आबंटित।
- प्रासाद योजना के तहत अयोध्या, मथुरा और वाराणसी में राम, कृष्ण और बुद्ध सर्किट।
- अर्द्ध-कुंभ मेला 2019 में विकास कार्य के लिए 510 करोड़ रू.।

सुशासन को लगा पंख :

- एक अक्टूबर से प्रदेश में ई-आफिस योजना लागू।
- बाढ़ राहत के लिए सरकार ने 454 करोड़ रू. दिए।
- सभी शासकीय कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग योजना लागू, 55000 ई-टेंडर जारी।

- 69 अपराधियों की सम्पत्ति जब्त की गई।
- 9973 अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाही।
- इलेक्ट्रानिक चिप लगाकर पेट्रोल चोरी करने वाले पेट्रोल पम्प सीज़ किये गये।
- 3 साल में पुलिस में होंगी 1.5 लाख नियुक्तियां।

भू –माफिया पर दृष्टि :

- तहसील, जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर एंटी भू माफिया टास्कफोर्स का गठन।
- भू–माफियाओं की 35 करोड़ रू. की सम्पत्ति जब्त की गई।
- 12,800 हेक्टेयर जमीनों से अवैध कब्जा हटवाया गया।
- जमीनों का डिजिटल डाटा बनना शुरू।

युवा कल्याण :

- 1000 करोड़ रू. का स्टार्टअप फंड गठित किया गया।
- 7 शहरों में आईटी पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर।
- अगले 5 वर्षों में युवाओं को 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर देने का लक्ष्य।
- आईटीआई में 4000 सीटों की बढ़ोतरी।
- 16 नए पॉलिटेक्निक एवं 15 छात्रावासों का निर्माण।
- लखनऊ में 1000 की क्षमता वाले कौशल विकास केन्द्र–2 का निर्माण तेजी से जारी।
- पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति 26 फीसदी बढ़ाकर रू. 510 करोड़ की गयी।
- दिव्यांगों के भरण–पोषण के लिए पेंशन धनराशि 300 रू. से बढ़ाकर अब 500 रुपये प्रतिमाह।